28 मई, 2015

विवादास्पद क्षेत्र में जापान तथा दक्षिण कोरिया

सी लालपेखलुई

नवीनतम स्थिति के अनुसार, जापान तथा दक्षिण कोरिया दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में ठंडापन आ गया है। मुख्य रूप से इसकी जड़ें जापान के औपनिवेशिक अतीत और उनके साझा इतिहास पर दृष्टिकोणों में मतभेद से संबंधित पुराने मुद्दों में निहित हैं। ये मुद्दे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही कोरियाई लोगों की संवेदनाओं में समाहित रहे हैं और यद्यपि दोनों देश अब जीवन्त लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं तथापि, ये अपने बीच के इन विवादास्पद मुद्दों को सुलझाने में असमर्थ रहे हैं। चिंता केवल इनके द्विपक्षीय संबंधों के बारे में ही नहीं है, बल्कि यह चिंता पूर्वोतर एशियाई क्षेत्र के लिए भी है, जो उत्तर कोरिया द्वारा आक्रमण की धमकियों और चीन की विस्तारवादी रणनीति के रूप में समस्याओं से ग्रस्त है।

दोनों एशियाई देशों के नेताओं – दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति सुश्री पार्क गुन हे और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच पहली सीधी बैठक 25 मार्च, 2014 को हेग में परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त समय में हुई थी। यह बैठक अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने करवाई थी।[1] जापान और दक्षिण कोरिया के बीच अच्छे संबंध के निर्माण में अमरीका का निहित स्वार्थ है, क्योंकि ये (दोनों देश) इस क्षेत्र में अमरीका के निकट सहयोगी हैं। उत्तर कोरिया की धमकियों को निरस्त करने और चीन की विस्तारवादी नीतियों को रोकने के लिए इनके बीच सहयोग अपेक्षित है। इस बैठक में एक विशेष महत्वपूर्ण परिणाम सामने आया अर्थात दोनों एशियाई नेताओं द्वारा अपने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने हेतु राजनयिक बैठक करने संबंधी करार (पर हस्ताक्षर)। राष्ट्रपति ओबामा क्षेत्रीय चिंताओं जैसे कि उत्तर कोरिया और चीन के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा प्रदान करने के बारे में आशावादी दिखे।

दोनों देशों के वरिष्ठ राजनयिकों के बीच एक महीने बाद 16 अप्रैल 2014 को सियोल में एक बैठक हुई और दोनों पक्षकारों द्वारा कतिपय करार किये गए:

- दोनों देश मासिक बैठकें करने पर सहमत हुए जो कम महत्वपूर्ण प्रकृति की होंगी।
- दक्षिण कोरिया ने अपने देश में जापान-विरोधी प्रदर्शनों को समर्थन देना बंद करने पर सहमति जताई।
- दोनों देशों के बीच अवस्थित द्वीपों पर क्षेत्रीय विवाद को प्राथमिकता में पीछे डाल दिया गया है।

यद्यपि इस बैठक से कोई भी महत्वपूर्ण नतीजा सामने नहीं आया, तथापि "परस्पर हित के मुद्दों" को सुलझाने के लिए एक महीने बाद एक और बैठक तय की गई। यह निश्चित रूप से सही दिशा में एक अच्छा कदम था, जो विशेष रूप से इसलिए आवश्यक था कि दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित "मित्रता करार" की 50वीं वर्षगांठ जून 2015 में आने वाली थी। हालांकि, यदि यथा-स्थिति बनी रही तो जापान और दक्षिण कोरिया इसका जश्न मनाने की मन:स्थिति में नहीं होंगे। इस मुद्दा सार में दक्षिण कोरिया और जापान के बीच मौजूदा स्थिति (के विश्लेषण) के साथ-साथ इन दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण स्थिति क्यों नहीं रह सकती, उन कारणों का विश्लेषण किया गया है। इस तथ्य को देखते हुए कि दोनों ही देश भारत के कूटनीतिक भागीदार हैं, दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंध का भारत की पूर्वी एशिया कार्यनीति पर प्रभाव पड़ेगा।

राजनीतिक परिदृश्य में, उन प्रमुख मुद्दों, जो आजकल चर्चा में हैं, में से एक मुद्दा दक्षिण कोरियाई "कम्फर्ट वूमेन" के प्रति जापान का रूख है, जो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और इसके दौरान जापानी सेना द्वारा यौन दासता में जबरन धकेली गई महिलाओं के लिये प्रयुक्त एक वाक्यांश है। प्रधानमंत्री आबे ने युद्ध काल के दौरान जापान की ज्यादतियों के लिए मांगे गए दो राष्ट्रीय क्षमा – कोनो वक्तव्य और मुरायामा वक्तव्य में संशोधन का सुझाव दिया था। वर्ष 1993 के कोनो वक्तव्य में यह स्वीकार किया गया है कि जापानी राजशाही सेना कम्फर्ट ठिकाने (फैसिलिटीज) स्थापित करने में संलिप्त थी जिसमें 'कम्फर्ट वूमेन' रखी गईं, जिसमें से ज्यादातर दक्षिण कोरिया की थीं। मोरायामा वक्तव्य में राजशाही जापानी (सेना) द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने एशियाई पड़ोसियों के प्रति की गई ज्यादतियों के लिए क्षमा मांगी गई। दक्षिण कोरिया इन्हें जापान द्वारा युद्ध के दौरान की अपनी भूमिका को नजरअंदाज़ करने के लिए किए गए प्रयास मानता है, जिसके कारण उनके बीच संबंधों में ठंडापन आ गया और राष्ट्रपति पार्क ने इस मुद्दे के रहने तक आबे के साथ द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन से इंकार कर दिया। प्रधानमंत्री आबे ने वर्ष 2014 में आश्वासन दिया कि उनका मंत्रिमंडल कोनो वक्तव्य के तथ्यों को बनाए रखेगा और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसने दक्षिण कोरिया और अमरीका के साथ त्रिपक्षीय वार्ताओं के लिए उत्प्रेरक का काम

किया। हालांकि इससे कोरियाई जनता के असंतोष को कम करने में बहुत ज्यादा सहायता नहीं मिली क्योंकि कोनो वक्तव्य पर जापानी पदाधिकारियों द्वारा बार-बार प्रश्न उठाए जाते रहे हैं।

एक अन्य विवादास्पद मुद्दा जापान में यासूकूनी मंदिर का मुद्दा है जहां न केवल युद्ध मृतकों को, बल्कि दोषसिद्ध अ-श्रेणी युद्ध अपराधियों को भी सम्मानित किया जाता है। जापानी कानून निर्माता और अधिकारीगण कथित शिंटो मंदिर की यात्रा करते रहे और प्रधानमंत्री आबे ने इस मंदिर के लिए अपना चढ़ावा भी भेजा, यद्यपि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गुटों के दबावों के कारण विगत वर्ष के विपरीत वर्ष 2014 में इसकी यात्रा नहीं की। सरकारी पदाधिकारियों द्वारा बार-बार किए गए यात्राओं ने दक्षिण कोरिया और चीन की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जो सम्मानित युद्ध अपराधियों के हाथों ज्यादतियों के शिकार हुए थे। इससे शायद दक्षिण कोरिया के साथ राजनयिक संबंध सुधारने के जापान के प्रयासों में बाधा पड़ सकती है। आबे सरकार के राष्ट्रवादी एजेंडे के साथ इतिहास के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोणों का भी मुद्दा विद्यमान है।

वर्ष 2014 के प्रारंभ में अमरीकी राष्ट्रपति ओबामा की सहायता से सम्पन्न त्रिपक्षीय विचार-विमर्श के पश्चात दोनों नेता अपने-अपने पदों पर दोबारा आने के बाद, द्विपक्षीय वार्ताओं के लिए अब तक नहीं मिले हैं। प्रधानमंत्री आबे ने दक्षिण कोरिया के साथ एक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन की आशाएं व्यक्त की थीं[2] लेकिन राष्ट्रपति पार्क ने शिखर सम्मेलन बैठक के लिए शर्तें थोप दी हैं, जैसे कि "इतिहास की सही-सही जानकारी" जो आबे के व्यक्तिगत राजनीतिक धारणाओं के विरुद्ध जाता है। यह घटना एक जापानी पत्रकार के संबंध में हाल की एक और घटना के दौरान घटित हुई है, जिस पर दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया गया है।[3]

इस (संबंधित) जापानी पत्रकार ने एक ऑनलाइन जापानी समाचार पत्र में एक लेख लिखा था, जिसमें उसने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की उपस्थिति के संबंध में प्रश्न उठाए थे जब 16 अप्रैल, 2014 को कोरियाई नौका दुर्घटना हुई थी और उसने संकेत दिया कि वे दुर्घटना के प्रारंभिक घंटों के दौरान अनुपस्थित रही थीं क्योंकि वे एक पुरूष से भेंट कर रही थीं, जो पूर्व सहायक था। हालांकि एक कोरियाई समाचार पत्र ने राष्ट्रपति की अनुपस्थिति अथवा किसी पुरूष के साथ संभावित रोमांस के संबंध में अफवाहों के बारे में सबसे पहले लिखा था, लेकिन केवल जापानी पत्रकार को ही दोषारोपित किया गया और उसे घर में नजरबंद कर दिया गया और देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस स्थिति ने दोनों देशों के बीच राजनैतिक संबंधों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के बारे में चिंताएं पैदा कर दी थीं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विश्वव्यापी वाद-विवाद भी हुआ।

रक्षा तथा सुरक्षा के विषय पर, दोनों एशियाई देशों के साझे इतिहास पर गतिरोध ने उनके बीच

लाभकारी द्विपक्षीय संबंध बनने में रूकावट डालना जारी रखा है। वर्ष 2012 में, जब ली म्युंग बाक राष्ट्रपति के पद पर आसीन थे, तब दोनों देश एक सैन्य सूचना संबंधी सामान्य सुरक्षा (जीएसओएमआईए) सौदे पर हस्ताक्षर करने ही वाले थे जिसके द्वारा व्यापक विनाश के परमाणु तथा अन्य हथियारों का उत्तर कोरिया द्वारा विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाता। यदि हस्ताक्षर हो जाते तो यह संधि दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक महत्व रखती और इसके माध्यम से मिलिट्री एक्वीजीशन एण्ड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट (एसीएसए) के लिए मार्ग प्रशस्त होना तय था। लेकिन इसके बाद से दोनों देशों के बीच परिस्थितियों का बिगड़ना जारी रहा और इस संधि पर हस्ताक्षर करना दक्षिण कोरिया द्वारा भविष्य में इसे पूरा करने के किसी वायदे के बिना ही स्थगित हो गया है।[4] यह दक्षिण कोरिया में मुखर सार्वजनिक असंतोष से प्रेरित था जहां एक जनमत सर्वेक्षण ने दर्शाया कि 48 प्रतिशत जनता ने जापान के साथ सैन्य संधि का विरोध किया।[5]

अमरीका की लगातार प्रेरणा से, अंतत: एक त्रिपक्षीय आसूचना साझा संधि पर अमरीका, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच 29 दिसम्बर, 2014 को हस्ताक्षर किया गया।[6] यह आसूचना साझा (संधि) उत्तर कोरिया की परमाणु तथा मिसाइल धमकियों पर पूर्णरूपेण केन्द्रित है और सियोल के रक्षा मंत्रालय के एक दक्षिणी कोरियाई अधिकारी ने एक समाचार-पत्र को सूचना दी कि गोपनीय (सूचनाएं) जापान के साथ सीधे तौर पर नहीं बल्कि अमरीका के माध्यम से साझा की जाएंगी।[7] जहां यह आसूचना साझा संधि दोनों एशियाई देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम को दर्शाता है, वहीं एक मध्यस्थ के रूप में अमरीका का उपयोग यह दर्शाता है कि जापान पर दक्षिण कोरिया का अविश्वास समाप्त नहीं हुआ है।

आर्थिक मोर्चे पर, दोनों देशों के बीच संबंध उतना मंद दृष्टिकोण प्रदर्शित करता प्रतीत नहीं होता, जितना राजनीतिक परिदृश्य में प्रदर्शित होता है। जापान दक्षिण कोरिया का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और सामरिक और अंतराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र (सीएसआईएस) के एशियाई कार्यक्रम के अनुसार "..... आर्थिक सहयोग और प्रतियोगिता ने दोनों देशों को हाल के वर्षों में उत्तरोत्तर एकीकृत तथा अधिक लाभप्रद बनाया है।[8] दक्षिण कोरिया ने वर्ष 2009 में जापान के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापार में 28 अरब डॉलर का घाटा सहा, लेकिन जब मूल्य संवर्धित दृष्टिकोण से इस व्यापार का आकलन किया जाता है तो यह घाटा लगभग 80 प्रतिशत कम हो जाता है। वर्ष 2014 में चीन के साथ-साथ जापान और दक्षिण कोरिया ने इस क्षेत्र में कुल मिलाकर राजनीतिक तनाव के बावजूद त्रिपक्षीय मुक्त व्यापार करार पर वार्ताएं जारी रखने के लिए बैठक की।[9] हालांकि वर्तमान में इस त्रिपक्षीय वार्ता का कोई उल्लेखनीय परिणाम निकलता प्रतीत नहीं होता, फिर भी ऐसी बैठकों का आयोजन प्रगति माना जा सकता है।

तथापि, द्विपक्षीय रूप से, आर्थिक परिस्थिति जल्दी ही डावांडोल होनी प्रारंभ हो सकती है। ऐसी

रिर्पोटें हैं कि दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा में गिरावट प्रदर्शित हुई है तथा यह वर्ष 2009 के बाद से अपने निम्नतम स्तर पर है,[10] और यह वर्ष 2014 के पूर्वाध में 43 अरब डॉलर था। हालांकि व्यापार में इस गिरावट के लिए तनावपूर्ण आर्थिक वातावरण को कारण के रूप में नहीं माना गया है, लेकिन यह स्वत: स्पष्ट हो गया है कि दक्षिण कोरिया जापान की बजाय चीन के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों पर ज्यादा जोर दे रहा है। दक्षिण कोरिया और चीन के बीच द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार संबंधी वार्ताएं सुचारू गति से आगे बढ़ रही हैं जिसमें दोनों देश निकट भविष्य में इस सौदे को अंतिम रूप देने के प्रति आश्वस्त हैं।[11] इसके साथ ही, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच मुक्त व्यापार करार वर्ष 2012 के बाद से पुन: प्रारंभ नहीं हुआ है।

अतीत में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों पर राजनीतिक तनावों का उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है। यह आंशिक रूप से जापानी और दक्षिण कोरियाई कम्पनियों के परस्पर संबंध और परस्पर निर्भरता के कारण (संभव) हुआ लेकिन दक्षिण कोरिया में हाल की गतिविधियों, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्व के दौरान दक्षिण कोरियाई कामगारों द्वारा जापान के विरुद्ध दर्ज किया गया मुकदमा, के साथ ही इस मजबूत आर्थिक बंधन में जल्दी ही संभावित दरार आ सकता है। जापान से होनेवाले आयातों पर दक्षिण कोरिया की घटती निर्भरता के कारण भी जापान पर दबाव है, जो वैश्विकरण के कारण हुआ है, जिसमें दक्षिण कोरिया के पास अधिक विकल्प उपलब्ध रहते हैं, जहां से वह अपनी जरूरत की कच्ची सामग्री प्राप्त कर लेता है।[12]

सामाजिक पहलू में, जनमत सर्वेक्षणों ने दर्शाया है कि दोनों देशों के बीच एक दूसरे के बारे में नकारात्मक विचारों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। जहां कोरिया द्वारा "जापान की आलोचना" को कारण बताते हुए आधे से अधिक जापानी प्रतिवादियों ने दक्षिण कोरिया के प्रति नकारात्मक भावनाएं होना स्वीकार किया है, वहीं दो तिहाई से अधिक दक्षिण कोरियाई प्रतिवादियों में जापान के प्रति नकारात्मक विचार होने की रिपोर्टें थीं क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि जापानियों में "आक्रमण के इतिहास पर अपर्याप्त पछतावा" है।[13,14] जापानियों में अभी भी एक आम धारणा मौजूद है कि दक्षिण कोरियाई सामान निम्न स्तर के हैं और दक्षिण कोरियाई भी इस आम धारणा से नहीं उबर पाए हैं कि जापानी अपने आप को उत्कृष्ट मानते हैं। इन गलत धारणाओं को दक्षिण कोरिया पर जापानी कब्जे से जोड़ा जा सकता है।

जापान में, उस देश में रहने वाले विदेशियों के प्रति घृणापूर्ण भाषण की मात्रा में वृद्धि हुई है।[15] इन घृणापूर्ण भाषणों और प्रर्दशनों के मुख्य लक्ष्य जातीय कोरियाई हैं जिसमें से अनेक कोरिया पर जापान के औपनिवेशिक शासन के दौरान जहाजों से जापान लाए गए बंधुआ मजदूरों के सीधे वंशज हैं। ओसाका उच्च न्यायालय ने इस निर्णय को कायम रखा है कि ऐसे घृणास्पद भाषण गैर-कानूनी हैं[16] और रैलियां जातिगत विचारों द्वारा उकसाई गई प्रतीत होती हैं और ये आम जनता की भावनाओं को चित्रित करती प्रतीत नहीं

होती हैं। ये विरोध प्रदर्शन सीमित संख्या में प्रतिभागियों द्वारा किये जाते हैं, अधिक से अधिक कुछेक सौ लोगों द्वारा और आम तौर पर ये प्रमुख शहरी क्षेत्रों से दूर छोटे क्षेत्रीय शहरों में आयोजित होते हैं जिसमें एक बार में औसतन 43 प्रदर्शनकारी होते हैं। ये दुर्भावनापूर्ण भावनाएं दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों में अंतर्निहित प्रतीत नहीं होती हैं और केवल राजनीतिक प्रकृति की प्रतीत होती हैं। इसी सर्वेक्षण ने दिखलाया कि 60.9 प्रतिशत कोरियाइयों के साथ-साथ 41.6 प्रतिशत जापानियों ने एक-दूसरे के देशों का दौरा करने की इच्छा व्यक्त की।[17]

जनसाधारण स्तर पर, लोगों के आपसी मेल-जोल (पी2पी) के संबंध में ऐसे संकेत हैं जो दर्शाते हैं कि जापान से दक्षिण कोरिया आने वाले आगंतुकों की संख्या में लगातार कमी आती रही है। हाल के आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2013 के सितम्बर माह की तुलना में वर्ष 2014 के इसी माह में पर्यटकों की संख्या में 20 प्रतिशत की कमी आई है।[18] तथापि, वर्ष 2014 में दक्षिण कोरिया[19] से जापान आने वाले आगंतुकों की संख्या में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन प्रतीत नहीं होता, क्योंकि कुल मिलाकर संख्याएं केवल थोड़े बहुत अंतरों, जो मौसमी प्रकृति के प्रतीत होते हैं, के साथ समान ही हैं।

इससे प्रदर्शित होता है कि दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंध/संपर्क तनावपूर्ण राजनैतिक वातावरण के बावजूद जारी है। जापान और कोरिया, दोनों देशों के बीच राजनैतिक संबंधों के सामान्य होने की 40वीं वर्षगांठ मनाने के लिये वर्ष 2005 में प्रारंभ हुआ जापान-कोरिया विनिमय महोत्सव का प्रत्येक वर्ष आयोजित होना जारी है जो दोनों देशों में बारी-बारी से आयोजित होता है। इस वर्ष यह महोत्सव टोकियो में हुआ था और कार्यक्रम बिना किसी रूकावट/गतिरोध के सम्पन्न हुए। जापान में दक्षिण कोरिया के राजदूत यू ह्यूंग सू ने उद्घाटन समारोह में अभिलाषा व्यक्त की कि यह कार्यक्रम नए दक्षिण कोरिया-जापान संबंधों के लिए प्रारंभिक बिंदु का काम करेगा।[20]

यद्यपि, दक्षिण कोरिया में जापानी टेलीविजन और नाटकों का प्रसारण करना अभी भी अवैध है, तथापि इंटरनेट की प्रगति के साथ ही जापानी लोकप्रिय संस्कृति दक्षिण कोरिया में भलीभांति प्रसिद्ध है और प्रमुख/मशहूर हस्तियों का उल्लेख कोरियाई टेलिविजन पर रोज हुआ करता है। कोरियाई वेव (Hallyu) का भी जापानी प्रमुख बाजार में प्रवेश करना जारी है। दक्षिण कोरिया के गायक हमेशा जापानी भाषा में एलबम और गीत निकालते रहते हैं। के-पॉप-समूह जापान में संगीत समारोह संबंधी यात्राएं करते ही रहते हैं और इस पहलू में किसी गिरावट की संभावना प्रतीत नहीं होती।

निष्कर्ष

वर्तमान में दक्षिण कोरिया और जापान के बीच राजनीतिक संबंध वर्ष 1965 में सामान्य होने के बाद से अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं। एक कार्यात्मक राजनैतिक संबंध के निर्माण में रूकावट बनने में ऐतिहासिक मतभेद अपनी भूमिका अदा करते रहते हैं। इस समस्या का कोई व्यवहार्य समाधान निकट भविष्य में निकलता प्रतीत नहीं होता। इसके कतिपय कारण इस प्रकार हैं:

पहला कारण, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि आर्थिक मामलों में दक्षिण कोरिया के लिए जापान का महत्व कम हुआ है और दक्षिण कोरियाई बाज़ार में निर्यातों पर जापान की निर्भरता बढ़ती प्रतीत हो रही है। असमतल आधारभूमि पर खड़े रहने के कारण दोनों देशों के लिए अपने संबंध को कोशिश करके फिर से ठीक करना कठिन हो रहा है। साथ ही, दक्षिण कोरिया ने चीन के साथ जारी अपने अच्छे संबंध को प्रोत्साहित करके और अंशत: कोरियाई वेब की सहायता से चीन में निवेशों को बढ़ाया है।

दूसरा कारण, दोनों देशों के राष्ट्रवादी समूहों द्वारा इतिहास का राजनीतिकरण करना है। जापान के राष्ट्रवादी समूहों ने जापान के पूर्व अधिकारियों द्वारा अपने इतिहास, जिस पर कोरियाई जनता अप्रसन्नता व्यक्त किया करती है, के संबंध में मांगी गई सार्वजनिक माफियों में संशोधन की मांग की है। साथ ही, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रवादी समूहों द्वारा प्रमुख चुनावों के दौरान बड़े पैमाने पर जनता के हाय-तोबा को उकसाकर अवसर मिलने पर अपने इतिहास, क्षेत्रीय विवादों आदि के संबंध में जापानियों पर आक्रमण करना जारी है।

तीसरा कारण, दोनों ही देशों में ऐसे सुदृढ़ राजनीतिक नेताओं की कमी प्रतीत होती है, जो जनता की प्रत्येक राय से प्रभावित न हों। उदाहरण के लिए, जीएसओएमआईए और एसीएसए करार उत्तर कोरिया से (मिलने वाली) धमकियों को रोकने में महत्वपूर्ण तंत्र माने गए थे और जो अमरीका के साथ त्रिपक्षीय सहयोग में बेहतर सहायता करते, लेकिन जनता द्वारा नकार दिये जाने के कारण इन्हें आगामी सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि दक्षिण कोरिया ने पहले ही रूस और अमरीका सहित 23 अन्य देशों के साथ इसी प्रकार की संधियों पर हस्ताक्षर किये हैं।

चौथा कारण, दोनों देशों के नेताओं की गहन राजनीतिक धारणाएं हैं, जो एक दूसरे के विपरीत हैं। जहां प्रधानमंत्री शिन्ज़ो आबे एतिहासिक धारणाओं में संशोधन की राजनीति अपनाते हैं, वहीं पार्क गुन हे जापानी प्रधानमंत्री के साथ किसी शिखर सम्मेलन के आयोजन से पहले एतिहासिक मतभेदों को सुलझाना एक प्राथमिकता मानती हैं।

दोनों देशों के लिए यह अनिवार्य आवश्यकता है कि वे अतीत के मुद्दों को पीछे छोड़ें और उन साझे मुद्दों को सुलझाने के लिए आगे बढ़ें जिसका सामना दोनों ही कर रहे हैं। जापान और दक्षिण कोरिया दोनों मुक्त बाजार के सिद्धांतों वाले जीवंत लोकतंत्र हैं। ये दोनों ही उत्तर कोरिया की ओर से साझा धमकियों का सामना करते हैं और इनकी अपनी-अपनी अर्थव्यवस्थाएं मंदी का सामना कर रही हैं। अमरीका के साथ साझा त्रिपक्षीय गठबंधन भी कमजोर है, क्योंकि दोनों देशों के बीच संबंध अभी भी उदासीन हैं। इस वर्ष 2015 में इनके बीच राजनयिक संबंधों के सामान्य होने की 50वीं वर्षगांठ आ रही है। दोनों में से किसी भी देश का अपने इतिहास के संबंध में भावनात्मक आवेग विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इनकी प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं होगा। एकमात्र सकारात्मक लक्षण, जिसे हमेशा कुछ हद तक नकारा गया है, जनसाधारण स्तर पर है जहां लोगों के आपसी संपर्क अभी भी मौजूद हैं और इसका फलना-फूलना जारी है। यह शायद एकमात्र संकेत हो सकता है कि भविष्य उतना धुंधला नहीं है जितना यह अभी प्रतीत हो रहा है।

***

**सी. लालपेखलुई विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली में अनुसंधान अध्येता हैं।*

समाप्ति नोट:

[1] थॉमस एस्कृत और स्टीव हॉलैंड, "ओबामा ने अमेरिकी मित्र राष्ट्रों दक्षिण कोरिया और जापान को वार्ताओं के लिए राजी किया", *रायटर*, 25 मार्च, 2014

[2] चोए संग हूँ "जापान के प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन की बैठक दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के साथ चाहते हैं", *न्यूयॉर्क टाइम्स*, 19 सितम्बर, 2014

[3] डॉ. राजाराम पांडा," जापान-दक्षिण कोरिया के संबंधों में रूकावट क्योंकि सियोल ने जापानी पत्रकार पर अभियोग लगाया – विश्लेषण" *यूरेशिया समीक्षा*, 16 अक्तूबर 2014

[4] जैसन स्ट्रोथेर, "एक आश्चर्यजनक कदम के रूप में, दक्षिण कोरिया ने जापान के साथ सैन्य खुफिया समझौता स्थगित कर दिया", *सीएस मॉनिटर*, 29 जून, 2012

[5] "सर्वेक्षण: 48% दक्षिण कोरियाई जापान के साथ सैन्य समझौते का विरोध करते हैं", [सियोल, जीजी प्रेस, 5 जुलाई, 2012]

[6] अंकित पांडा, "अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान के बीच उत्तर कोरिया पर आसूचना भागीदारी प्रारंभ का दी", *द डिप्लोमैट*, 30 दिसंबर, 2014

[7] ओह सिओक मिन, "दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान उत्तर कोरिया पर जानकारी साझा करने संबंधी समझौता करने वाले हैं", *योनहैप समाचार*, 26 दिसंबर, 2014

[8] डेविड ए. पार्कर और मिखाइल लिंडफोर्स, "अर्थशास्त्र और जापान-कोरिया संबंध: बढ़ता महत्व", *कोजिट एशिया*, 12 मार्च 2014

[9] शान्नोन टीएज़्ज़ी, "चीन-जापान-दक्षिण कोरिया राजनीतिक तनाव के बावजूद एफटीए वार्ता करेंगे", *द डिप्लोमैट*, 5 मार्च, 2014

[10] "कोरिया और जापान के बीच वर्ष 2014 में व्यापार में गिरावट आई", *अरिरंग समाचार*, 19 अगस्त, 2014

[11] कांगक्यू ली, "चीन-दक्षिण कोरिया एफटीए पर चर्चा निष्कर्ष के करीब", एशिया ब्रीफिंग, 10 अक्तूबर 2014

[12] हिदेहिको मुकोयामा, "आर्थिक संबंधों पर एक अस्थिर जापान-दक्षिण कोरिया रिश्ते का असर: अब जापान को क्या करना चाहिए?" [अर्थशास्त्र विभाग, जापान अनुसंधान संस्थान]

[13] "जापान, कोरिया के बीच आपसी नापसंद बढ़ रहा है", *द वॉल स्ट्रीट जर्नल,* 11 जुलाई 2014

[14] द्वितीय संयुक्त जापान-कोरिया सार्वजनिक जनमत सर्वेक्षण (2014) - तुलनात्मक आंकडों पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, "सकारात्मक-नकारात्मक धारणाओं के पीछे का कारण [ईएआई (पूर्वी एशिया संस्थान), 2014]

[15] रूईची कितनो , ' नफरतपूर्ण भाषण का विरोध जापान के आसपास छोटे शहरों तक फैलने रहा है', *द असही शिम्बुं,* 7 नवम्बर 2013

[16] "ओसाका अदालत ने स्कूल के बाहर कोरिया-विरोधी नफरततपूर्ण भाषण पर पाबंदी लगाने के फैसले को कायम रखा", *जापान टूडे,* 9 जुलाई 2014

[17] "जापान, कोरिया के बीच आपसी नापसंद बढ़ रहा है", द वॉल स्ट्रीट जर्नल, 11 जुलाई 2014

[18] कोरिया, पर्यटन के मासिक आँकड़े [कोरिया पर्यटन संगठन]

[19] "देश/क्षेत्र के आधार पर आगंतुकों का आगमन और जुलाई 2014 के लिए यात्रा का उद्देश्य", जापान राष्ट्रीय पर्यटन संगठन

[20] "टोकियो में जापान-दक्षिण कोरिया विनिमय महोत्सव 2014", *क्योदो समाचार,* 27 सितम्बर 2014.